Conducting national level competitions in all disciplines of sports and identifying extraordinary talent of the Tamil Nadu youth needs Government of India's priority in the promotion of sports in India.

Need to reconsider the proposal for cancellation of the stoppage of Rajdhani Express at Naugachhia in Bihar

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : महोदय, अखबारों में छपा है कि 12423/12424 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1 अक्टूबर से नौगछिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी। नौगछिया स्टेशन से इस ट्रेन के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग बन्द कर दी गई है, इसलिए अब नौगछिया तथा भागलपुर के यात्रियों को इस ट्रेन को पकड़ने के लिए पटना जाना पड़ेगा। इस कारण तमाम सांसदों, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को दिल्ली पहुंचने में परेशानी होगी। महोदय, 11 मार्च, 2012 से यह राजधानी ट्रेन नौगछिया स्टेशन पर रुक रही थी, किन्तु अचानक अब इसका ठहराव बन्द करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसमें नौगछिया के लिए एसी-3 की छः सीटें, एसी-2 दो सीटें व एसी-1 की दो सीटें आरक्षित थीं, जिससे यहां के लोगों को बड़ी सहूलियत थी और इससे रेलवे को फायदा भी था, क्योंकि सारी सीटें भर जाती थीं। दिल्ली से नौगछिया जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस व बह्मपुत्र मेल पांच घंटे ज्यादा समय लेती हैं और इसके बन्द हो जाने से उनमें भीड़ भी बढ़ जाएगी।

अतः मेरी रेल मंत्रालय से गुज़रिश है कि राजधानी एक्सप्रेस 12423/12424 के नौगछिया स्टेशन पर ठहराव को रद्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और इसका ठहराव बहाल किया जाए, जिससे यहां के यात्रियों को हो रही भारी परेशानी से बचाया जा सके।

Demand to take concrete steps to curb the increasing incidents of missing of women and children in Madhya Pradesh

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : मध्य प्रदेश में महिलाएं और बच्चे अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले पांच वर्षों में महिलाओं और बच्चों के लापता होने की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत 2010 में बच्चों के लापता होने की 440, 2011 में 517, 2012 में 630, 2013 में 748 और वर्ष 2014 में मई माह तक 406 घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाओं के मामले में वर्ष 2013 में 3209 प्रकरण दर्ज हुए और 2014 में मई मत 2904 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। शायद यह सब मानव तस्करी के लिए किया जा रहा हो।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार से परामर्श कर ठोस कदम उठाये, ताकि मध्य प्रदेश में महिलाएं और बच्चे अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

Demand to take steps to prevent encroachment and misuse of land belonging to Defence Forces in the country

SHRI AMBETH RAJAN (Uttar Pradesh): Sir, large extent of land is under the control of the Defence establishment. An estimate states that 17.31 lakh acres of land is under the control of the Defence Ministry. Out of this, 1.57 lakh acres of land is situated within the 62 notified Cantonments. About 15.96 lakh acres of land is situated outside the